कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

सरकार की उपलब्धियां

69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र संबोधन.............................. 7

संगठनात्मक गतिविधियां

परिवर्तन रैली : गया.. 9

आरा.. 11

सहरसा.. 12

वैचारिकी :

उपयुक्त उम्मीदवार कौन होता है?

– **पं. दीनदयाल उपाध्याय**.. 13

श्रद्धांजलि

संगठन शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे.. 15

प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा

भारत और यूएई द्वारा आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा........................ 16

दुबई के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधन....... 19

लेख

क्या यह भारत का नुकसान है?

– **अरुण जेटली**.. 26

व्यष्टि व समष्टि और एकात्म मानववाद

– **डॉ. विजेन्द्र सिंह गुप्त**.. 27

अन्य

बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज – 2015.................................. 22

नगरीय निकाय चुनावों में खिला कमल.. 30

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

बोध कथा

शुभ संकल्प को एक पल के लिए भी स्थगित नहीं करना चाहिए

युधिष्ठिर को बड़ी हैरानी हुई। नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, ये विजय दुंदुभि क्यों बज रहे हैं?

भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेना ने तो कोई विजय प्राप्त नहीं की है। पर पता चला है कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। सुनकर युधिष्ठिर की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है! आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?

भीम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा कि वह कल मिले। तब उसकी समस्या और हल आप सुनेंगे। इससे जाहिर है कि आज तो मृत्यु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ब्राह्मण से आपका संवाद सुनने के बाद मैंने सोचा कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ही ली है, वरना आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए कतई नहीं कहते। यह सोचकर मैंने नगाड़े बजाने की आज्ञा दी थी।

भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का पता लगा। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने याचक से उसकी आवश्यकता के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि अगले शुक्लपक्ष में उसकी बेटी का विवाह है। खर्च के लिए कुछ भी पास में है नहीं। कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही। ब्राह्मणी ने कहा कि धर्मराज के पास जाओ। वह अवश्य कोई प्रबंध कर देंगे।

ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मराज ने ब्राह्मण की जरूरत के लिए यथेष्ट प्रबंध कर दिया। फिर भीम से वह बोले, क्षमा करना। मैं इस बात से चूक रहा था कि शुभ संकल्प को एक पल के लिए भी स्थगित नहीं करना चाहिए।

- जयरामदास दीन

(अमर उजाला से साभार)

पाथेय

राष्ट्र का संगठन

राष्ट्र का संगठन किन्हीं स्वार्थों की पूर्ति के लिए उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य शरीर में जिस प्रकार सभी अवयव स्वाभाविक ही क्रियाशील हैं, इसके लिए उन्हें शाबासी या प्रलोभन नहीं देना पड़ता। उसी प्रकार राष्ट्र के घटक भी राष्ट्र की सेवा के लिए परस्पर अनुकूल व्यवहार करते हुए इसके संगठन को बनाए रखते हैं। एक राष्ट्रभाव की विस्मृति के कारण घटक अंग शिथिल पड़ते हैं और यदि पूरी तरह निष्क्रिय हो गए तो संपूर्ण राष्ट्र के विनाश के कारण भी बनते हैं। किंतु यदि इन घटकों में राष्ट्रभाव का जागरण हो जाए तो वे पुनः स्वाभाविक क्रिया में संलग्न हो उठते हैं। अतः हमें कालजयी, स्थायी, सक्षम, आत्मनिर्भर, व्यावहारिक और स्वाभाविक संगठन के लिए राष्ट्र को ही आधार मानना होगा। राष्ट्र का संगठन दृढ़ हुआ तो सामर्थ्य निर्माण होगा और विभिन्न अंग पुष्ट हो सकेंगे।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

लाल किले की प्राचीर से...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधन से हमारी राजनैतिक व्यवस्था एवं लोकतंत्र में जनविश्वास और दृढ़ हुआ है। उन्होंने पुनः इस बात पर बल दिया कि 'विकास' ही वह मंत्र है जिससे साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद की समस्या को दूर किया जा सकता है। 'विकास के अमृत से साम्प्रदायिकता और जातिवाद को मिटाना है'– इस कथन का पुरजोर स्वागत होना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की भागीदारी पर बल दिया। यह एक ऐसा सच है जिसे बोलते तो सभी राजनैतिक नेता हैं पर पालन बहुत कम ही करते हैं। प्रधानमंत्री ने जहां 'जनभागीदारी' के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है वहीं mygov.in, मन की बात, लाखों पत्र एवं जनसंवाद के माध्यम से इसका पालन भी किया है। वास्तव में उन्होंने लोकतंत्र को प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाया है क्योंकि वे जानते हैं कि भारत सफलता को तभी चूम सकता है जब लोकतंत्र सफल होगा।

अपने संबोधन में उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों एवं प्रतिबद्धताओं को भी रेखांकित किया। यह सच है कि जन धन योजना आज सरकार की एक बड़ी उपलब्धि न केवल इस मायने में है कि 17 करोड़ बैंक एकाउंट खुल गये बल्कि इसलिए भी कि ये रिकार्ड समय में खोले गये। उन्होंने लोगों को स्मरण दिलाया कि पिछले 15 अगस्त को उन्होंने समयबद्ध तरीके से इस योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया था और आज वे गर्व से कह सकते हैं कि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। आर्थिक समावेशन के महत्व की चर्चा करते हुए उन्होंने विकास की उस पिरामिड के विषय में कहा जिसका सबसे निचला आधार सबसे चौड़ा है और जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और उपेक्षितों से बना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ग के लिए बैंक खातों के माध्यम से आर्थिक समावेशन का द्वार खोल इन्हें मजबूत करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्व की सबसे वृहत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जो इस देश के गरीब से गरीब के लिए उपलब्ध है– उसकी भी चर्चा की। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना– ये तीन महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे बीमा एवं पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का तंत्र सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ने भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और इसके लिए उन्होंने बच्चों को सबसे अधिक धन्यवाद दिया जिन्होंने परिवार के अंदर और बाहर इस अभियान के 'ब्रांड अंबेस्डर' के रूप में एक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने 'श्रमेव जयते' योजना की भी चर्चा की जिसने असंगठित क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की भूमिका तैयार की है तथा अनेक सुरक्षा योजना के माध्यम से श्रमिकों का सम्मान सुनिश्चित किया है। श्रमिक कानूनों का सरलीकरण कर 44 कानूनों को 4 आचार संहिता में समेट कर इन्हें श्रमिक हितैषी एवं सुगम्य बनाया गया है।

भ्रष्टाचार के विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के अपने संकल्प को दोहराया तथा कम समय में लिए गये अनेक पहलों की चर्चा की। गैस सिलेंडर को डीबीटी योजना में लाकर इस पूरे तंत्र को न केवल भ्रष्टाचार मुक्त किया गया बल्कि 15000 करोड़ रुपये बचाये भी गये हैं जबकि सरकार की अपील पर 20 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है। कोयला खदानों में नीलामी से 3,00,000 करोड़ रुपया देश के खजाने में जमा हुआ है तथा इस पारदर्शी व्यवस्था से स्पैक्ट्रम की नीलामी में भी काफी लाभ हुआ है। उन्होंने काला धन के विषय में भी चर्चा की तथा जी-20 में इसे उठाने के संबंध में बताया। काला धन पर बने कड़े कानून से यह तो सुनिश्चित हो ही गया है कि अब काला धन देश के बाहर नहीं भेजा जा सकेगा जबकि विदेशी बैंकों में जमा काला धन को वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है।

महंगाई पर नियंत्रण सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है वह भी तब जबकि पिछले वर्ष वर्षा कम हुई थी। मुद्रास्फीति जो दहाई आंकड़े तक रहा करती थी अब पूरे नियंत्रण में है और इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

गांव, किसान, जवान, युवा, दलित, आदिवासी और महिलाओं से संबंधित लगभग हर विषयों पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ध्यान आकर्षित किया। किसानों तथा कृषि से संबंधी अनेक विषयों को उठाते हुए प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि कृषि मंत्रालय के नाम के साथ 'किसानों का कल्याण' भी जोड़ा जाएगा जो इस मंत्रालय

का एक मुख्य कार्य होगा। जहां एक ओर किसानों को पर्याप्त बिजली एवं पानी देने की व्यवस्था की जा रही है वहीं 18,500 गांव जिन्होंने कभी बिजली का तार और खंभा तक नहीं देखा उन्हें एक हजार दिनों के अंदर बिजली से जोड़ा जाएगा। 'स्टार्ट अप इंडिया' और 'स्टैण्ड अप इंडिया' जैसे अनूठे कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए उन्होंने देश भर के 1,25,000 बैंक शाखाओं से अपील की कि हर शाखा एक दलित या आदिवासी तथा एक महिला को ऋण देकर इन वर्गों से उद्यमियों को खड़ा करे। यह डा. भीमराव अंबेडकर को 125वीं वर्ष में श्रद्धांजलि होगी। जो भारत में पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनसे भी उन्होंने अपील की कि वे अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करें और इसके लिए उन्हें सरकार विशेष पैकेज देगी। उन्होंने छोटे नौकरियों में 'साक्षात्कार' के प्रावधान हटाने की अपील की और कहा इससे भ्रष्टाचार दूर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 'वन रैंक, वन पेंशन' को सरकार सिद्धांतत: स्वीकार कर चुकी है और जल्द ही सुखद समाचार प्राप्त होगा।

पिछले एक वर्ष में भारत हर क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। कार्य संस्कृति में परिवर्तन देखा जा रहा है तथा सरकारी तंत्र उत्साहजनक वातावरण में परिणामकारक कार्य में जुट गये हैं। देश के सर्वांगीण विकास एवं विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर अनेक अभिनव योजनाएं परिणाम दे रही हैं। बंद पड़े एवं अवरूद्ध योजनाएं पुनर्जीवित की गई हैं और देश में नकरात्मकता एवं निराशा का माहौल खत्म हो गया है। किसान से श्रमिक, कुशल से अकुशल, रोजगार प्राप्त से बेरोजगार- सब सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में है। मोदी सरकार ने आशा एवं विश्वास का एक नया युग प्रारंभ किया है। लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी का अवसर देकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को प्रोत्सहित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के संबोधन से भविष्य के लिए आशा एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ हुआ है तथा लोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान देने को उत्सुक हैं। देश को सरकार के द्वारा किये गये कार्यों से अवगत करा विभिन्न क्षेत्रों में हुए तीव्र प्रगति से परिचित कराया गया। लोगों की अपेक्षा को नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयास के द्वारा दिन-रात के कार्य से पूर्ण करने के प्रयास हुआ हैं ताकि भारत विश्व में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़कर भारत को विकसित, समृद्ध, भ्रष्टाचार मुक्त तथा वैभवशाली राष्ट्र बनाने की उनकी अपील हरेक के दिल को छू रही है। प्रधानमंत्री के संबोधन ने न केवल राष्ट्र को प्रेरित किया है बल्कि वैभवशाली भविष्य के लिए नई ऊर्जा से भर दिया है। ■

भाजपा मुख्यालय में ध्वजारोहण

कंधे से कंधा मिलाकर देश सेवा का संकल्प लें : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय परिसर 11 अशोक रोड, नई दिल्ली में 69वें स्वतत्रंता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया और राष्ट्रध्वज को सलामी दी।

इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों तथा भाजपा के देश भर के कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा लोगों से देश के लिए मर मिटने का संकल्प करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए देश की आन, बान और शान के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया तथा वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

उन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों की सहर्ष आहुति देने वाले वीर शहीदों का स्मरण करते हुए कहा कि यह उन्हीं के बलिदानों का फल है कि आज भारतवर्ष स्वतंत्र है और यहाँ विकास के नित नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। श्री शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं और देश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि आप सब कंधे से कंधा मिलाकर देश सेवा का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार भारत में विकास के एक नई इबारत लिख रही है और हम सब को उन्हें हर कदम पर उनका भरपूर साथ देना चाहिए।■

सरकार की उपलब्धियां : 69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र संबोधन

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भ्रष्टाचार खत्म करने तथा 2022-स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 125 करोड़ भारतीयों की टीम इंडिया का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में टीम इंडिया की उपलब्धियों का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ भारतीयों की एकता, सादगी और भाईचारा इस देश की मजबूती है और हमारे समाज में जातिवाद और संप्रदायवाद का कोई स्थान नहीं है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त का यह सवेरा मामूली सवेरा नहीं है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वातंत्र्य पर्व का सवेरा है। यह सवेरा, सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपनों का सवेरा है। यह सवेरा सवा सौ करोड़ देशवासियों के संकल्प का सवेरा है और ऐसे पावन पर्व पर जिन महापुरूषों के बलिदान के कारण, त्याग और तपस्या के कारण सदियों तक भारत की अस्मिता के लिए जूझते रहे, अपने सर कटवाते रहे, जवानी जेल में खपाते रहे, यातनाएं झेलते रहे, लेकिन सपने नहीं छोड़े, संकल्प नहीं छोड़े। ऐसे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों को मैं आज कोटि-कोटि वंदन करता हूं। पिछले दिनों हमारे देश के अनेक गणमान्य नागरिकों ने, अनेक युवकों ने, साहित्यकारों ने, समाजसेवियों ने, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, विश्व भर में भारत का माथा ऊंचा करने का अभिनंदनीय कार्य किया है। अननिगत वो लोग हैं, जिनको मैं आज लालकिले के प्राचीर से भारत का माथा ऊंचा करने के लिए हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि किस तरह राजग सरकार की पहल से शासन के विभिन्न पक्षों से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। उन्होंने इस संदर्भ में कोयला, स्पेक्ट्रम तथा एफएम रेडियो लाइसेंस की नीलामी की चर्चा की। उन्होंने एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए पहल योजना की चर्चा की जिससे 15 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि नीम चढ़ी यूरिया से सब्सिडी यूरिया को गैर कृषि उद्देश्यों में लगाने के काम को रोकने में मदद मिली है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि आम जन को अभी भी भ्रष्टाचार के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को दीमक बताते हुए कहा कि इसके इलाज के लिए साइट इफेक्ट के प्रभाव के साथ कड़वी दवा की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने सरकार के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि कैसे इन प्रयासों से बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पिछले वर्ष भ्रष्टाचार के 1,800 मामलें दर्ज हुये, जबकि इससे पहले के वर्ष में 800 मामले दर्ज हुये थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार बनने के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट मार्गदर्शन में एसआईटी बना दी। तीन साल से लटका हुआ काम हमने पहले ही सप्ताह में पूरा कर दिया, वो एसआईटी आज काम कर रही है। मैं जी-20 समिट में गया, दुनिया के वो देश वहां मौजूद थे, जिनकी मदद से काला धन वापस आ सकता है। जी-20 समिट में भारत के आग्रह पर काले धन के खिलाफ प्रस्ताव किया गया और हर देश एक-दूसरे को मदद करेगा, काला धन देशों को वापस पहुंचाने के लिए संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने विश्व के कई देशों के साथ काले धन की जानकारी प्राप्त करने हेतु संधियां की है, ताकि वे देश अपने पास भारतीय नागरिकों के काले धन की जानकारियां हमें शीघ्र उपलब्ध कराते रहें।

उन्होंने कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छ भारत को हमें उन्हें अर्पित करना है। महात्मा गांधी को 150वीं जयंती पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और इसलिए अभी तो काम शुरू हुआ है लेकिन मुझे इसको आगे बढ़ाना है। इसको रोकना नहीं है, संतोष मानना नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है और विदेशों में जाने वाली बिना हिसाब

'टीम इंडिया' भ्रष्टाचार के दीमक को खत्म करेगी,

- **सरकार की पहल से विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार दूर हुआ**
- **किसानों के कल्याण, कृषि उत्पादकता पर बढ़ाने पर बल**
- **'एक रैंक-एक पेंशन' सिद्धांत रूप में स्वीकार, तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं**
- **स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पर जोर**

किताब की आय को रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण की जरूरत पर जोर दिया और घोषणा की कि कृषि मंत्रालय का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का जोर कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बिजली उपलब्ध कराने तथा किसानों को सिंचाई सुविधा देने पर है। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई है।

प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में व्यक्त कुछ संकल्पों की भी याद दिलायी। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में शौचालय बनाने का वायदा राज्यों के सहयोग से लगभग पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 17 करोड़ बैंक खाते खोले जाने से वित्तीय समावेशन को बढ़ा प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि जनधन खातों में जमा 20 हजार करोड़ रुपये गरीबों की अमीरी दिखाते है।

प्रधानमंत्री ने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सहित सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बच्चों को स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेस्डर बताया और कहा कि इस अभियान से भारत के लोगों में गहरी रुचि पैदा हुई।

प्रधानमंत्री ने 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख बैंक शाखाओं में से प्रत्येक शाखा को एक दलित या एक आदिवासी उद्यमी या कम से कम एक महिला उद्यमी को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'स्टैंड-अप इंडिया'। पूर्व सैनिकों की 'एक रैंक, एक पेंशन' की पुरानी मांग के बारे में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि इस मांग को सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ तौर-तरीकें तैयार किये जा रहे है। उन्होंने सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने 2022 तक भारत को सभी के लिए मकान तथा बिजली जैसे बुनियादी सुविधायें देकर विकसित देश बनाने का सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने आने वाले एक हजार दिनों में बिजली से वंचित 18,500 गांवों को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के सरकार के संकल्प को व्यक्त किया। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास के विजन को भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने कनिष्ठ स्तरों पर भर्तियों में साक्षात्कार के व्यवहार पर प्रश्न उठाते हुए संबद्ध विभागों से जल्द से जल्द इस व्यवहार को समाप्त करने तथा पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रियाओं के जरिये भर्ती करके मेधा को प्रोत्साहित करने को कहा। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : परिवर्तन रैली, गया

'बिहार में विकास रूपी परिवर्तन की बयार लाइए'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 अगस्त को गया (बिहार) के ऐतिहासिक गांधी मैदान से परिवर्तन रैली का शंखनाद करते हुए एक विशाल जन-समूह को सम्बोधित किया।

उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में बिहार की जनता ने जिनके हर जुल्म, अहंकार, जंगलराज और धोखाधड़ी को झेला है, यह चुनाव उनसे मुक्ति का पर्व

बनकर आने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में फिर से जंगलराज पार्ट-II की वापसी हुई तो बिहार के नौजवान का भविष्य तबाह हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में राज्य का भला करने वाली अहंकारमुक्त, जंगलराज मुक्त और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार बननी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने बिहार में बंद पड़े उद्योग कारखाने की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि मैंने पिछले दिनों बिहार आकर कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया लेकिन यहाँ सत्ता के मद में चूर शासकों का ध्यान इस ओर कभी नहीं गया।

उन्होंने बिहार में विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव बाद यह गठबंधन कितना चलेगा, इसमें संदेह है। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि बिहार में भुजंग प्रसाद और चंदन कुमार कौन है? प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी सियासी फायदे के लिए यह गठबंधन किया गया है और चुनाव के बाद जब ये लोग जहर उगलेंगे, तो यह जनता की थाली में पड़ेगा। उन्होंने जनता को इन लोगों से आगाह करते हुए कहा कि जिन्होंने जहर पीया है, उनको जहर उगलने का मौका नहीं देना चाहिए।

बिहार में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बोध गया और गया में पर्यटन की अपार सम्भावना जताई और कहा कि पर्यटन का बिहार के विकास में एक अभूतपूर्व योगदान होगा।

बिहार में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक

बिहार के कानून-व्यवस्था की खस्ता हालत पर प्रहार करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सुबह सबेरे राज्य की राजधानी पटना में सरकार के नाक के नीचे भाजपा के एक कार्यकर्ता को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। यह जंगलराज की शुरुआत नहीं तो और क्या है? उन्होंने लोगों को जनता दल (यूनाईटेड) और राजद गठबंधन की परिभाषा बताते हुए कहा कि एक तरफ तो आरजेडी है जिसका सीधा मतलब होता है ''रोजाना जंगलराज का डर'' और दूसरी तरफ है जेडीयू जिसका मतलब होता है ''जनता का

- **बिहार में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं**
- **बिहार में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक**
- **बिहार में प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत सबसे कम**
- **बिहार में तकनीकी शिक्षा की हालत दयनीय**
- **बिहार ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया**
- **पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन**
- **आरजेडी है का मतलब है ''रोजाना जंगलराज का डर'' और जेडीयू का मतलब ''जनता का दमन और उत्पीड़न''**

दमन और उत्पीड़न''। उन्होंने जनता से कहा कि अगर इनका गठबंधन यानी जंगलराज पार्ट-II फिर से बिहार में आया तो तो सब बर्बाद हो जाएगा।

बिहार में प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत सबसे कम

बिजली देने के वादे को पूरा न करने पर प्रधानमंत्री ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में बिहारवासियों को अँधेरे में रखा है। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग की मात्रा सबसे कम है।

बिहार में तकनीकी शिक्षा की हालत दयनीय

प्रधानमंत्री ने बिहार में तकनीकी शिक्षा के खस्ता हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि बिहार में तकरीबन 80 लाख छात्र 17 से 20 वर्ष की आयु वाले हैं पर बिहार में इंजीनियरिंग में केवल 20 हजार सीटें हैं जबकि देश के अन्य छोटे - छोटे राज्यों में भी यहाँ से ज्यादा सीटें हैं। बिहार को तेजस्वी लोगों और विद्वानों की भूमि बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों को अच्छी तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें उचित अवसर मिलना चाहिए।

अपने उद्‌बोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि आप हमें विकास के लिए वोट दें, बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाने के लिए वोट दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं सवा कदम चलूंगा, अत: चुनाव में भारी मतदान के जरिये बिहार विकास रूपी परिर्वतन की बयार लाइये। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने गया, बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में परिवर्तन रैली में उपस्थित अपार जन-सैलाब को सम्बोधित करते हुए राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने राज्य में 15 साल जंगलराज का अनुभव किया और 15 साल तक बिहार पूरे देश में जंगलराज के नाम से बदनाम होता रहा। अपने भाषण के अंत में रैली को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि आज 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन बिहार की जनता संकल्प ले कि जंगलराज बिहार छोड़कर जाएगा और यहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग की सरकार बने।■

हमारी राजनीति और परम्परा ही विकास की रही है : अमित शाह

पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पटना में जागरण समूह द्वारा आयोजित 'जागरण फोरम' के समापन सत्र पर राज्य के बुद्धिजीवियों तथा पत्रकारों को सम्बोधित किया।

उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के होने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि बिहार आने वाले लम्बे समय किस प्रकार कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सही और सटीक फैसला ले लेता है तो मुझे विश्वास है कि केवल पांच वर्षों में ही बिहार अग्रिम राज्यों की प्रथम पंक्ति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव को मुद्दों के आधार पर ही लड़ा जाना चाहिए और बिहार में चुनाव का मुद्दा 'बिहार का विकास' और बिहार में एक 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की स्थापना पर केंद्रित होना चाहिए और इस दिशा में जागरण फोरम का यह प्रयास सर्वथा उचित और सराहनीय है।

उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड), राजद और कांग्रेस के गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि श्री नीतीश कुमार जिन्होंने लगातार 20 वर्षों तक लालू के जंगलराज के विरोध की राजनीति की और जिसके सहारे वह राज्य की सत्ता तक पहुंचे, केवल स्वार्थ के लिए आपने लालू जी से हाथ मिला लिया जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सजा हो चुकी है? भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि आपने लालू जी को 15 वर्ष दिए, कांग्रेस को भी आपने एक लम्बा समय दिया, आपने नीतीश जी को भी देखा - अब भाजपा को भी एक मौका दीजिये और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि केवल पाँच वर्षों में हम बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देंगें।■

संगठनात्मक गतिविधियां : आरा में विशाल रैली

सिर्फ पश्चिमी राज्यों के विकास से काम नहीं चलनेवाला पूर्वी राज्यों का भी विकास जरूरी

प्रधानमंत्री ने बिहार को दिया सवा लाख करोड़ का पैकेज

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 अगस्त को आरा में बिहार के लिए विशेष पैकेज का एलान किया। आरा के रमना मैदान में केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने आये प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए सवा लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सवा लाख करोड़ की यह राशि में राज्य पहले से चल रही 40,657 करोड़ की सड़क और बिजली परियोजनाओं के अतिरिक्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुल मिला कर बिहार के हिस्से 1.65 लाख करोड़ रुपये आयेंगे।

अपने 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ बिहार को विशेष पैकेज दे गये, बल्कि युवाओं को कौशल विकास और नये रोजगार का वादा भी किया। प्रधानमंत्री ने नये राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद से आरा की जनता को रू-ब-रू कराया और साथ आये केंद्रीय मंत्रियों का उत्साहवर्धन भी किया। जब उन्होंने सवा लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का एलान किया, तो भीड़ ने खूब तालियां बजायीं और मोदी-मोदी के नारे लगाये। प्रधानमंत्री ने भोजपुरी में अपने संबोधन का आरंभ करते हुए जैसे ही कहा कि रउरा सब लोग के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के बाद हम भोजपुर आइल बानी, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर रउरा लोगन के बहुत-बहुत प्रणाम। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बीती रात दुबई यात्रा की भी चर्चा की।

श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने पचास हजार करोड़ रुपये के पैकेज का वादा किया था, लेकिन, जब दिल्ली की सत्ता में आया और वहां की बारिकियां देखीं, तो पता चला कि बिहार का काम सिर्फ पचास हजार करोड़ रुपये से नहीं चलनेवाला। उन्होने उपस्थित भीड़ से पूछा कि पचास या साठ हजार करोड़ रुपये से काम चलेगा, भीड़ ने कहा नहीं। भीड़ का मिजाज देख वह आगे बढ़ते गये। बात 90 हजार करोड़ तक गयी। भीड़ ने जब कहा नहीं, तो अचानक प्रधानमंत्री रुके और वीर कुंवर सिंह व जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए सवा लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बिहार की चिर-प्रतिक्षित विशेष पैकेज की घोषणा के साथ-साथ नेशनल हाइवे की 97000 करोड़ की से 11 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने 878 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा सड़क का उद्घाटन किया और कौशल विकास योजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री यहीं नहीं ठहरे, उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने बिहार को 12 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया था। उनमें 8282 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। प्रदेश में नेशनल हाइवे की 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त बांका जिले में 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से बिजली कारखाना लगने वाला है। सबकी रकम होती है 40,657 करोड़, यह राशि बिहार को सवा लाख करोड़ रुपये की रकम से अतिरिक्त होगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मंच पर बैठ से सभी केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता भी खड़े हो गये और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि

दोनों रकम को जोड़ दिया जाये, तो बिहार को मिलनेवाले विशेष पैकेज की राशि हो जाती है 1.65 लाख करोड़। उन्होंने बिहारवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अपने इस वादे को हर हाल में पूरा करके रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को अब तक दो पैकेज मिले। पहला, झारखंड के अलग हो जाने के बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया। बाद में दिल्ली की सरकार बदल गयी। हालात बदल गये। कड़वा सत्य यही है कि 2013 तक इस 10 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की राशि भी बिहार की सरकार खर्च नहीं कर पायी।

प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो पश्चिमी राज्य के विकास से काम नहीं चलनेवाला। पूर्वी राज्यों को भी विकास करना होगा। उन्होंने बिहार, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, आसाम और पूर्वोतर राज्यों के नाम लिये।

मेक इन इंडिया के साथ-साथ स्किल इंडिया

इसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, वे बिहार का शक्ल, सूरत और भाग्य बदल देंगी। बिहार के नौजवानों को अद्‌भुत क्षमता देंगी और उन्हें ताकत देंगी। इस मौके पर राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री रामविलास पासवान, सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह, आइटी और संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, पेट्रोलियम राज्यमंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय लघु, सूक्ष्म उद्योग राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय पेयजल राज्यमंत्री श्री रामकृपाल यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री नंदकिशोर यादव, आरा के सांसद श्री आरके सिंह और स्थानीय विधायक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन श्री राजीव प्रताप रूडी ने किया। ■

'अगर कोई जनता को दुख पहुंचाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा की परिवर्तन रैली को मैथिली में संबोधित करते हुए कहा कि सभी को मोदी का प्रणाम। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले कोसी में आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई थी। 35 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए 7-8 जिले तबाह हो गए थे। हमने उस समय गुजरात से कोसी के लिए मदद की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि

मैं कोसी नदी की सौगंध खाकर कहता हूं कि किसी व्यक्ति का अहंकार मुझे इतनी चोट पहुंचाता है या कोई मुझे गाली देता है तो मैं सह लेता हूं, लेकिन अगर कोई जनता को दुख पहुंचाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री ने नीतीश द्वारा गुजरात से भेजी गई राशि को लौटाने पर कहा कि मैंने मेहनत की कमाई को जमाकर 5 करोड़ रुपए कोसी पीड़ितों के लिए भिजवाए थे, लेकिन इनका अहंकार इतना था कि इन्होंने वो रकम लेने से इनकार कर दिया और कोसी के लोग मरते रहे, लेकिन अहंकार के कारण उन्होंने आप सभी को पीड़ा सहने पर मजबूर कर दिया। मैं अपमान का जहर पी गया, लेकिन क्या ऐसे अहंकारी को रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण को जेल में किसने बंद किया। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आन्दोलन छेड़ा तो क्या अंजाम हुआ। किन लोगों ने जेपी को मरने दिया, जिसने जेपी को धोखा दिया और विश्वासघात किया और जिसने जेपी को तबाह किया आज उन्हीं का गठबंधन हुआ है। क्या ये दोषी हैं या नहीं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल लोग जनता को फेस नहीं कर पा रहे इसलिए एसी कमरे में बैठक करते हैं। हम तो जनता के सामने जाकर हिसाब देते हैं। सहरसा में प्रधानमंत्री ने बिहार में बढ़ रहे अपराध का जिक्र बिहार सरकार के आंकड़ों के द्वारा किया। उन्होंने कहा कि हत्या, दंगों पर अगर अंकुश लगाना है तो पटना में हमारी मदद कीजिए। श्री मोदी ने कहा कि मैंने बिहार का भाग्य बदलने और नया बिहार बनाने के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया है इससे काफी हद तक बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। ■

उपयुक्त उम्मीदवार कौन होता है?

✍ पं. दीनदयाल उपाध्याय

राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए चुने गए प्रत्याशियों के गुणावगुण के बारे में 4 दिसम्बर 1961 को 'आर्गनाइजर' में छपा एक लेख जिसका हिन्दी अनुवाद हम अपने सुधी पाठकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं:

सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में घोषित आम चुनावों के कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। ज्योतिषी चाहे जो भी भविष्यवाणी करें, लोग और राजनैतिक पार्टियों को गम्भीर होना पड़ेगा और उन्हें इस महान लोकतांत्रिक चुनावों की तैयारी के काम पर लगना होगा। पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। जहां कुछ पार्टियों ने, विशेष रूप से, कांग्रेस को विरोधाभासी दावों के बीच किसी मान्य समझौते पर कठिनाई महसूस हो रही है, नई पार्टियों को भी उनके प्रतीक पर चुनाव लड़ने के लिए 'उपयुक्त' उम्मीदवारों को लड़ने के लिए कहीं अधिक प्रयास करने पड़ रहे हैं। 'उपयुक्त' उम्मीदवार एक ऐसा शब्द है जिसकी रक्षा करने की अपेक्षा समझने की कहीं अधिक जरूरत है। किन्तु देश और पार्टियों की राजनैतिक हालत को सही ढंग से समझने के लिए उम्मीदवारों के प्रमुख गुणावगुणों पर चर्चा करना अधिक बेहतर होगा।

किसी सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो विधान मण्डल में पार्टी के विचारों को सही ढंग से पेश कर सके, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र को भली-भांति पोषण कर रहा हो और वह अपने लोगों की भावनाओं को पेश करने का दावा कर रहा हो। व्यक्ति के रूप में वह लोगों के प्रति काम में कार्यरत हो और पार्टी के सदस्य के रूप में वह प्रतिनिधित्व करता हो, अनुशासित हो तथा अपने काम के प्रति समर्पित हो। यदि उसके पास अन्य कोई योग्यताएं हो तो वे उसकी उपयुक्तता में इन गुणों में चांद लगाने का काम करेगी।

परन्तु भारत में शायद ही कोई राजनैतिक पार्टी हो जो इस सम्बन्ध में चिंता करती हो। उनका एक ही ध्येय होता है कि पार्टी को विजय मिलनी चाहिए। रेस लगाने वालों की तरह उन्हें किसी खास घोड़े से प्यार नहीं होता है। वे केवल उसी घोड़े पर दांव लगाएंगे जिसके जीतने के अवसर अत्यंत उज्ज्वल हों। परन्तु वे भूल जाते हैं कि राजनीति में विजयी होने का सम्बन्ध खेलने के बाद समाप्त नहीं हो जाता है। उन्हें यह बोझ लगातार उठाना पड़ता है और उसके माध्यम से ही पार्टी को विधान मण्डल में और निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करना आवश्यक होता है।

आज अधिकांश राजनैतिक पार्टियों की कोई जमीनी जड़ नहीं है। कांग्रेस, जो कभी वास्तविक रूप में लोगों पर पकड़ रखती थी, आज उसकी यह पकड़ समाप्त हो चुकी है। नई पार्टियों को अभी भी परिश्रम करना है ताकि वे लोगों की प्रिय पार्टी बन सके। इन हालात में पार्टी के अपील के अलावा अन्य लोगों की अपील भी जरूरी हो गई है। इसी कारण से हर पार्टी पूर्व-राजाओं के साथ सम्पर्क में लगी रहती है। यहां तक कि यदि कोई सत्ताधारी पार्टी का सदस्य चुनाव लड़ रहा हो तो मंत्री भी विरोध करने से कतराते हैं। और यदि वे कांग्रेस का साथ निभाना चाहते हैं तो सभी अन्य विरोधी उम्मीदवार अपनी विजय पर आशंकित रहते हैं।

यह मानते हुए भी कि पूर्व-शासकों को चुनाव में लड़ने का नागरिक अधिकार है तो भी यह मानना होगा वर्तमान हालात खुशगवार नहीं है। इस स्थिति को

पूर्व-शासन सुधार नहीं सकते हैं परन्तु यह सुधार तो लोगों तथा विभिन्न पार्टियों को ही करना होगा। पूर्व राजकुमार व्यवस्था को निश्चित ही राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, परन्तु चुनाव में टिकट देना केवल उनके जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। लोगों को भी यह समझना चाहिए कि वोट कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसके माध्यम से कोई उम्मीदवार अपना आभार प्रगट कर सके बल्कि ये अपनी इच्छाओं को पूरी करने का जनादेश है।

जाति तथा सामुदायिक विचार भी उम्मीदवारों के चयन में बड़ा भाग अदा करते हैं। इस बारे में कांग्रेस सबसे अधिक पापी है परन्तु अन्य पार्टियां भी इससे बची नहीं हैं। इसका कारण सुस्थिर और ठोस संगठन की कमी है। जातिवाद को कोसने से कोई लाभ नहीं होगा। जो अन्य पार्टियां भी अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं, वे भी इस पर विश्वास करती है। भारत में हर व्यक्ति का किसी न किसी जाति या समुदाय से सम्बन्ध रहता है। किसी अन्य पार्टी को जातिवाद या समुदायवाद में फंसे रहने के आरोप लगाने से आप अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देते हैं और अनजाने में ही समाज को शेष संवेदनाओं की अपील करते हैं। पिछले चुनाव के अनुभव से पता चलता है कि जिन उम्मीदवारों ने जातिगत भावनाओं को उभारा, उन्होंने शत्रुता को ही आमंत्रित किया और शेष संयुक्त विरोधी दलों का सामना करना पड़ा और इस प्रकार वे चुनाव बुरी तरह हार गए। परन्तु फिर भी यह विचार राजनीतिक पार्टियों पर हावी है। यदि अन्य मूल योग्यताएं वहीं है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उम्मीदवार किसी जाति से सम्बन्ध रखता है। वह कम से कम भारत में जाति विहीन नहीं बना रह सकता है। परन्तु, यदि स्थिति इस हद तक पहुंच जाती है कि डा. राम मनोहर लोहिया को भी अपनी उम्मीदवारी से इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह किसी जाति से सम्बद्ध नहीं थे जो उस समय उत्तर प्रदेश के उस उप-चुनाव में हावी थी (यह कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में थी), जो निश्चित ही एक बड़ी बुराई थी।

जो पार्टियां प्रमुख पार्टियों के रूप में तैयार होना चाहती हैं, उन्हें शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों की बलि नहीं देनी चाहिए। लोगों का भी कर्तव्य है कि वे अपने वोट का इस्तेमाल समझबूझ और सही ढंग से करें जिससे वे राजनीतिक पार्टियों के विकृत विचारों को सही दिशा प्रदान कर सकें।

वित्तीय रूप से एक और तत्व भी है जो उम्मीदवार चयन को प्रभावित करता है। ऐसे कुछ लोगों को टिकट दे दिया जाता है जिनके पास धन खर्च करने के अलावा कोई और योग्यता नहीं है। ये लोग चुनाव के समय ही मैदान में आते हैं और वे कलकत्ता और बम्बई की भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पांच वर्ष तक जमे रहते हैं। वे लोगों के पास वोट मांगने नहीं आते हैं, बल्कि वे वोट खरीदते हैं। उनके लिए इसकी कोई भी कीमत ऊंची नहीं होती है। उनके लिए यह उनका कारोबार होता है। कांग्रेस सहित सभी पार्टियां वित्तीय रूप से इतनी अधिक मुश्किल में होती हैं कि वे इन महत्वाकांक्षी प्रत्याशियों को सत्ता और ख्याति के लिए टिकट देकर आभार व्यक्त करने के लिए तैयार रहती है। समझा जाता है कि कांग्रेस ने कलकत्ता में कुछ उद्योगपतियों के साथ कुछ पार्लियामेंट सीटों पर ऐसा समझौता किया कि यदि वे विधान सभा चुनावों को चुनाव बिलों का धन देने का वायदा करें तो उन्हें टिकट दे दिया जाएगा। स्वतंत्र पार्टी सामान्य रूप से दलाल स्ट्रीट की पार्टी के रूप में जानी जाती है। पार्टियों की वित्तीय कठिनाई इस तरह से भारी पड़ती है कि गणतंत्र परिषद को केवल इसी कारण से स्वतंत्र पार्टी में अपना विलय करना पड़ा।

इस प्रकार के सभी तत्व राजनीति को गलत दिशा में ले जाते हैं। यदि इनमें सुधार के उपाय नहीं किए गए तो शक्तिशाली 'लाबी' देश के विधान मंडलों में अपना पैर जमा लेंगी तथा राजनीतिक निर्णय शायद ही उद्देश्यपूर्ण ढंग तथा लोगों के कल्याण एवं राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए ले सकें।

जो पार्टियां प्रमुख पार्टियों के रूप में तैयार होना चाहती हैं, उन्हें शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों की बलि नहीं देनी चाहिए। लोगों का भी कर्तव्य है कि वे अपने वोट का इस्तेमाल समझबूझ और सही ढंग से करें जिससे वे राजनीतिक पार्टियों के विकृत विचारों को सही दिशा प्रदान कर सकें।

मतदाताओं को शिकायत नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो कमान की स्थिति में होना चाहिए। उन्हें इच्छा नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें मांग की स्थिति में होना चाहिए। उन्हें शिकायत की स्थिति में न होकर पूरी तरह से दबाव बनाने की स्थिति में होना चाहिए। मतदाताओं को देखना चाहिए कि वह सिद्धांत के लिए वोट देता है, न कि किसी पार्टी को वोट

देता है। यह भी कि वह किसी व्यक्तित्व को देख कर वोट नहीं देता है, कि वह किसी व्यक्ति को वोट देता है, न कि किसी व्यक्ति के पर्स को देखकर वोट देता है।

उसे कारण पर विचार करना चाहिए, न कि किसी जाति के आधार पर, उसे योग्य व्यक्ति को वोट दे न कि कौन जीतता या हारता है। वह सही व्यक्ति को चुने और देखे कि जिस व्यक्ति को वह वोट देना होता है, वह विजयी हो, ऐसी विजय आपकी विजय होगी। यदि आप केवल ऐसे व्यक्ति के अनुयायी होंगे जिसने ऐसा भाव पैदा कर दिया हो कि वह विजयी रहेगा तो यह आपकी ही हार होगी, चाहे फिर चुनाव का जो भी परिणाम निकले। वोट एक जागृति का विषय है। इसे बेचिए नहीं। इसे खराब मत कीजिए। जब आप वोट देते हैं तो वह पल एक महान निर्णय का पल होता है, इसे केवल एक ही पल में न लें, समझबूझ कर लें।

वोट एक व्यक्तिगत अधिकार है जिसे समाज को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। इससे आपकी स्वतंत्रता का ध्यान आता है, इसे स्वतंत्र होकर निर्णय लीजिए। यदि आप डेमोक्रेट हैं तो किसी के कहने पर मत जाइए बल्कि अपनी आत्मचेतना से निर्णय लीजिए। जो राजनैतिक दल लोगों के लिए होते हैं। वे ही लोगों की शक्ति बन कर भी उनके साथ होते हैं। यदि लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुझाए नहीं तो लोगों को अपनी शक्ति उनके हाथों सौंपनी होगी।

यह लोग ही है जो राजनैतिक दलों के आर्किटेक्ट हैं और उनके माध्यम से वे अपनी नियति का निर्माण करते हैं। उन्हें अपने सामने खड़ी इस महान परीक्षा में सफल होना ही चाहिए। ■

संगठन शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे

शत-शत प्रणाम!

श्री कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के धार नगर में हुआ। उनके पिता डा. सुन्दर राव श्रीपति राव ठाकरे तथा माता श्रीमती शांता बाई सुन्दर राव ठाकरे थीं। उनकी शिक्षा दीक्षा धार और ग्वालियर में हुई। 1942 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और उसके बाद वे रतलाम प्रभाग (रतलाम), उज्जैन, मंदसौर, झाबुआ, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवान (राज.), दाहौड़ (गुजरात) में चले गए। श्री कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपने आप को समर्पित कर दिया था। वह एक ऐसे सच्चे कार्यकर्ता के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने पार्टी में बड़े पद पर रहे परन्तु वे सदैव जमीन से जुड़े रहे और विचारधारा तथा संगठन के प्रति समर्पित रहे।

रा.स्व.सं. और जनसंघ: 1942 से ही श्री कुशाभाऊ ठाकरे रा.स्व.सं. सम्बद्ध रहे। वह नीमच (म.प्र.) में 1942 से प्रचारक रहे और इसके बाद रतलाम प्रभाग (रतलाम), उज्जैन, मंदसौर, झाबुआ, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाडा (राज.), दाहौद (गुजरात) चले गए।

भारतीय जनसंघ में इन वर्षों के दौरान उनकी यात्रा की एक झलक:

1956 प्रारम्भ से ही सचिव (संगठन) मध्य प्रदेश।

1967 अखिल भारतीय सचिव, भारतीय जनसंघ, उड़ीसा और गुजरात का अतिरिक्त प्रभार।

1974 अखिल भारतीय सचिव (संगठन)।

1977 अध्यक्ष, मध्य प्रदेश जनता पार्टी।

1977 आपातकाल में 19 महीने तक जेल में।

1979 मध्य प्रदेश के खंड 95 से उपचुनाव में लोकसभा के लिए निर्वाचित।

1980 भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सचिव और गुजरात, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के प्रभारी व 1984 तक इस पद पर बने रहे।

1984 से 1986 तक : अखिल भारतीय उपाध्यक्ष।

1986 से 1991 तक : अखिल भारतीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी।

1991 से 1993 तक : उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी।

1993 : महासचिव (संगठन) और मध्य प्रदेश प्रभारी।

1998 से 2000 तक : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

28 दिसम्बर 2003 को स्वर्गवास। ■

भारत में संयुक्त अरब अमीरात करेगा 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश

भारत और यूएई द्वारा आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा

सामरिक महत्व वाले खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात की 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी यूएई गई थीं। यूएई में करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खाड़ी देश को 'मिनी-इंडिया' कहते हुए इसे अपने दिल के काफी करीब बताया। उन्होंने कहा कि 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यहां आना काफी अनोखी बात है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 अगस्त को दो दिनों की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे थे। वह पिछले 34 वर्षों में यूएई की यात्रा पर आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। श्री मोदी की इस यात्रा के दौरान जो सहमति बनी उसके अनुसार यूएई भारत में 75 अरब डॉलर का निवेश करेगा। उल्लेखनीय है कि यूएई के साथ भारत के सम्पूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग महत्वपूर्ण आयाम है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध पारंपरिक तौर पर काफी करीबी और दोस्ताना हैं जो आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण गठजोड़ के रूप में उभरे हैं।

भारतीय, यूएई में महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में उभरे हैं और भारत, यूएई निर्मित उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण निर्यात स्थल बनकर सामने आया है। भारत और यूएई के बीच कारोबार 1970 के दशक में 18 करोड़ डालर था जो अब बढ़कर करीब 60 अरब डॉलर हो गया है। यूएई से भारत को आयात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, बहुमूल्य धातुएं, रत्न, आभूषण, खनिज और रसायन आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं।

यूएई पहुंचने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 'हैलो यूएई'। मैं इस यात्रा को लेकर बहुत आशान्वित हूं। मुझे भरोसा है कि इस यात्रा के परिणामों से भारत-संयुक्त अरब अमीरात रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, एयरपोर्ट में मेरी अगवानी करने आए शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायेद अल

नह्यान की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं।

अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूएई की ऐतिहासिक शेख जायेद मस्जिद गए। यह यूएई की प्रमुख इबादतगाहों में से एक है और यह इस्लामी वास्तुशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहां उन्होंने सेल्फी भी ली। यह मस्जिद सउदी अरब के मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका नामकरण यूएई के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति दिवंगत शेख जायेद बिन सुल्तान अल नह्यान पर रखा गया।

मंदिर बनाने को अबु धाबी में जमीन देगी यूएई सरकार

प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस यात्रा के दौरान यूएई सरकार ने अबु धाबी में एक मंदिर के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला किया। यूएई की राजधानी में निर्मित होने वाला यह पहला मंदिर होगा। इस 'ऐतिहासिक' निर्णय के लिए पीएम मोदी ने यूएई नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया।

श्री मोदी यूएई में भारतीय कामगारों से भी मुखातिब हुए, उनकी समस्याएं जानी और इन तरीकों पर चर्चा की कि भारत सरकार उनकी मदद कैसे कर सकती है। श्री मोदी आई-कैड रेजिडेंशियल लेबर कैंप में भारतीय कामगारों से रूबरू हुए। इस कैंप इलाके में भारतीय उप-महाद्वीप से आए हजारों कामगार रहते हैं। कैंप का यह इलाका एक वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है। निचले स्तर के कामगारों से मुखातिब होने के अलावा मोदी ने उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतुम के साथ वार्ता की जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। श्री मोदी ने भारत में निवेश के माहौल के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंधों को और गति प्रदान करने के रास्तों पर विचार विमर्श किया, साथ ही संबंधों के सभी आयामों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2014-15 में चीन और अमेरिका के बाद यूएई, भारत का तीसरा सबसे बढ़ा व्यापारिक साझेदार है।

यूएई ने भारत द्वारा व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में नयी पहल किये जाने के चलते इसे निवेश के नये अवसरों वाला देश स्वीकार किया और दोनों देशों ने यूएई की निवेश संस्थाओं द्वारा भारत में उनके निवेश को बढ़ाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय किया। इसके लिए यूएई-भारत ढांचागत कोष का गठन होगा जिसका लक्ष्य इसे 75 अरब डालर तक करने का रखा गया है। इससे भारत में रेलवे, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डा, औद्योगिक गलियारे और पार्क जैसी नयी पीढ़ी की आधारभूत संरचना को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी।

दोनों नेता भारत-यूएई संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी में बदलने और रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, नौवहन सुरक्षा तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए यूएई के समर्थन पर उस देश का आभार जताया। मोदी ने यूएई की अल आइन में पश्चिम एशिया का पहला अंतरिक्ष शोध केंद्र स्थापित करने और 2021 में मंगल अभियान की योजना का स्वागत किया। दोनों देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने का निर्णय किया जिसमें उपग्रहों का संयुक्त विकास और प्रक्षेपण शामिल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूएई के शहजादे श्री मोहम्मद बिन जायेद अल नह्यान के बीच हुई वार्ता के बाद जारी 31 बिन्दुओं वाले संयुक्त बयान में राज्य प्रायोजित आतंकवाद सहित सभी स्वरूपों वाले आतंकवाद का विरोध किया गया है। दोनों देश आतंकवाद के विरूद्ध अभियानों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, खुफिया जानकारी साझा करने और इस संबंध में क्षमता उन्नयन करने पर सहमत हुए। श्री मोदी और श्री शहजादे नह्यान कुछ समूहों और देशों द्वारा नफरत फैलाने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को उचित ठहराने तथा कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए धर्म के दुरूपयोग के खिलाफ मुहिम चलाने में समन्वय बनाने पर भी सहमत हुए।

इससे पहले श्री मोदी ने यूएई के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत में अभी एक हजार अरब डालर के निवेश की संभावना है और सरकार इस देश के कारोबारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठायेगी और पिछले 34 वर्षों की 'कमी' को दूर करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएमएफ, विश्व बैंक और मूडी जैसी सभी प्रमुख वैश्विक संस्थाएं इस बात से सहमत हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसमें विकास की अपार क्षमताएं

हैं।

भारत और यूएई ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी तक ले जाते हुए उन देशों की कड़ी भर्त्सना की जो अन्य देशों के विरूद्ध आतंकवाद को प्रयोजित कर रहे हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा और विरोध किया और सभी देशों का आह्वान किया कि वे अन्य देशों के विरूद्ध आतंकवाद की नीति का त्याग करें। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के आधारभूत ढांचे को ध्वस्त करने और आतंकवाद के षड्यंत्रकर्ताओं को न्याय के कटघरे में खड़े करने की बात कही।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूएई के शहजादे श्री मोहम्मद बिन जायेद अल नह्यान के बीच हुई वार्ता के बाद जारी 31 बिन्दुओं वाले संयुक्त बयान में राज्य प्रायोजित आतंकवाद सहित सभी स्वरूपों वाले आतंकवाद का विरोध किया गया है। दोनों देश आतंकवाद के विरूद्ध अभियानों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, खुफिया जानकारी साझा करने और इस संबंध में क्षमता उन्नयन करने पर सहमत हुए। श्री मोदी और श्री शहजादे नह्यान कुछ समूहों और देशों द्वारा नफरत फैलाने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को उचित ठहराने तथा कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए धर्म के दुरूपयोग के खिलाफ मुहिम चलाने में समन्वय बनाने पर भी सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने किसी भी जगह और किसी के भी द्वारा उकसाये गए आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा करते हुए सभी देशों का आह्वान किया कि वे अन्य देशों के विरूद्ध आतंकवाद के इस्तेमाल को अस्वीकार करें और त्यागें। दोनों देशों ने जहां भी आतंकवाद के आधारभूत ढांचे हैं, उन्हें ध्वस्त करने और आतंकवाद के षड्यंत्रकर्ताओं को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का आह्वान किया।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने कानून अनुपालन, कालेधन और मादक पदार्थों तथा सीमा पार से होने वाले अन्य अपराधों के खिलाफ आपसी सहयोग और प्रत्यर्पण व्यवस्था कायम करने पर भी सहमति जतायी। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश उग्रवाद और धर्म एवं आतंकवाद के बीच किसी तरह के संबंध को नामंजूर करते हैं। वे किसी देश सहित किसी के भी ऐसे प्रयासों की निंदा करते हैं जिसमें आतंकवाद को प्रायोजित करने, समर्थन करने और उसे उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया हो।

बयान में कहा गया कि दोनों देश पश्चिम और दक्षिण एशिया में कुछ देशों द्वारा राजनीतिक मुद्दों और विवादों को साम्प्रदायिक एवं संकीर्ण रंग देने और अपने उद्देश्यों के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करने की निंदा करते हैं। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों में नैसर्गिक सामरिक गठजोड़ की असीम संभावनाएं हैं। ■

दुबई के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधन

भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संयुक्त अरब अमीरात की दो दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में दुबई के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में उपस्थित 50000 से अधिक भारतीय प्रवासियों के विशाल हुजूम को संबोधित किया।

अपनी चिर-परिचित शैली में भाषण की शुरुआत करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं दुबई में एक लघु भारत देख रहा हूँ और आप सब रोजी-रोटी कमाने के साथ-साथ अपने व्यवहार से देश का गौरव बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और भारत अपने आपको इस जनशक्ति से गौरवान्वित महसूस करता है।

उन्होंने लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में किये गए न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान जब पूरे विश्व जगत ने हर तरह का आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिया था तो वाजपेयी जी ने दुनिया भर में फैले भारतीयों से देश की मदद करने का आह्वान किया था और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि वाजपेयी जी के कहने पर भारत की तिजोरी भरने में खाड़ी देशों में मजदूरी करने वालों ने अहम भूमिका अदा की थी।

उन्होंने लोगों को पिछले लोक सभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि देश जब लोकसभा चुनाव में व्यस्त था और नतीजे आ रहे थे तो हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरा दुबई भी नाच रहा था और यह प्यार भारत माता के कल्याण के लिए, मां भारती एक बार फिर समृद्ध बने, ये सपना संजोने वाले आप लोग मेरे सामने बैठे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दुबई की प्रशंसा करते हुए कहा कि दुबई अब एक लघु भारत ही नहीं, एक लघु विश्व बन गया है और यहाँ विकास की जो तेज गति है, इसमें एक ऐसी चुम्बकीय आकर्षण शक्ति है जिसके कारण पूरा विश्व अनायास ही इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है तथा दुनिया भर से लोग यहाँ आना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी ने खचाखच भरे स्टेडियम में उपस्थित प्रवासी भारतीय लोगों को आजादी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दीं और साथ ही उन्होंने मलयाली में केरल के लोगों को भी केरल के नववर्ष की बधाई दी।

उन्होंने कहा कि हर हफ्ते भारत से

दुबई के लिए 700 से अधिक हवाई उड़ानें होती हैं लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 34 साल लग गए। उन्होंने कहा कि कभी-कभी मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से अच्छे काम हैं, जो मेरे पूर्व के लोग मेरे लिए छोड़कर गए और इसलिए मुझे यह अच्छे काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मेरा दुबई आना भी उन अच्छे कामों में से एक है।

अबू धाबी में अपने स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं इससे पहले कभी यहां नहीं आया था और 34 साल बाद जब प्रधानमंत्री के रूप में कोई आए तो किसी को भी नाराजगी व्यक्त करने का हक बनता है, लेकिन अबू धाबी में क्राउन प्रिंस ने और दुबई में हिज हाइनेस अल मकतुम जी ने नाराजगी नहीं दिखाई बल्कि इतने प्यार की वर्षा की कि जिसका वर्णन संभव नहीं है और मैं उनके इस प्यार को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस अपने सभी पांचों भाइयों के साथ एयरपोर्ट पर मुझको लेने के लिए आए इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि यह प्यार और यह सम्मान नरेन्द्र मोदी का नहीं, बल्कि यह 125 करोड़ भारतीयों और भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, यह उसका सम्मान है।

मंदिर के लिए जगह दिए जाने के फैसले का स्वागत

संयुक्त अरब अमिरात में मंदिर बनाने के लिए जगह दिए जाने के हिज हाईनेस प्रिंस के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक तरफ जहाँ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हैं, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जब हर तरफ चिंता का माहौल हो तो ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का फैसला किया है।

विश्वास, भरोसे और निवेश के लिए धन्यवाद

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमिरात के बीच जो विश्वास का माहौल बना है, वह आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान में साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है और यह दिखलाता है कि हमारे सम्बन्ध में कितना भरोसा है तथा यह कितना मजबूत एवं प्रगाढ़ है। उन्होंने कहा कि आज भारत की साख बनी है और भारत का बदलता स्वरुप विश्व के सामने अपनी स्वीकृति तेज गति से बनाता जा रहा है।

पाकिस्तान को आतंकवाद पर दो टूक

आतंकवाद पर जम कर बरसते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब मैं कहता था कि आतंकवाद गंभीर समस्या है तो सब कहते थे कि यह तो आपकी स्थानीय कानून और व्यवस्था की समस्या है। उन्होंने कहा कि आज लोग समझ रहे हैं कि यह कितनी विकराल समस्या है।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है - हम सबको मिलकर आतंकवाद को समूल नष्ट करना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएई के समर्थन के लिए धन्यवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और संयुक्त अरब अमिरात के साझा घोषणापत्र पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमिरात के शीर्ष नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने का फैसला किया है और इसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

पड़ोसियों के साथ आपसी सौहार्द्र, शांति और विकास की पहल

अपने पड़ोसियों से अच्छे और घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से किये गए प्रयासों पर बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि नेपाल को ही लीजिये, वह हमारा पड़ोसी है, वह दुखी हो और हम सुखी हों, यह संभव नहीं।

बांग्लादेश के साथ हुए सीमा समझौता पर बोलते हुए कहा कि हमने वहां भी वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद को बातचीत के जरिये हल किया और हिंसा की संभावनाओं को निरस्त किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने श्रीलंका के जाफना का दौरा किया और उन्हें वर्षों से चली आ रही खून-खराबे से पीड़ित मछुआरे भाई-बहनों का आंसू पोंछने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा कि जब मालदीव में मशीनें खराब होने की वजह से पीने का पानी की किल्लत हुई तो हमने बिना किसी देरी के तब तक पीने के पानी की आपूर्ति की जब तक कि वहां पानी की मशीनों ने काम करना शुरू नहीं कर दिया।

अफगानिस्तान के साथ मजबूत हुए आपसी संबंधों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा सहयोगी है, हम साथ मिलकर विकास की ओर बढ़ रहे हैं

और हम इसी तरह से दोस्ती बनाकर, सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। हम इसी कोशिश में जुटे हैं।

सार्क देशों के साथ सहयोग

सार्क देशों के बीच मधुर हुए सौहार्द्रपूर्ण संबंधों पर बोलते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पहले सार्क ऐसा मंच था, जहां पर एक–दूसरे को घेरने की कोशिश की जाती थी लेकिन अब साथ मिलकर कुछ अच्छा और बेहतर करने की कोशिश हो रही है।

प्रवासी भारतियों के लिए शुरू की गई योजनाएं

प्रधानमंत्री ने दुबई में बसे प्रवासी भारतीयों की दूतावासों में होने वाली परेशानियों के बारे में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है और इसलिए सरकार ने 'मदद' नाम से एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की है ताकि आपके समस्या का तुरंत निदान हो सके।

उन्होंने कहा कि समस्याओं के तत्काल हल के लिए सरकार ने ई–माईग्रेट पोर्टल भी तैयार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दूतावासों से कहा है कि महीने में कम–से–कम एक या दो बार भारतीय समुदाय के बीच जाकर उनके समस्याओं का निबटारा करने की कोशिश करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष (इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, आइसीएडब्ल्यूएफ) की स्थापना की है और हरेक दूतावासों को इस कोष की कुछ राशि दी है ताकि मुश्किल में फंसे गरीब और मजदूर भारतीय प्रवासियों को कानूनी और अन्य तरह की सहायता कानून के दायरे में रहकर कर की जा सके।

अपने उद्बोधन के अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, बस खून का रंग काफी है, मिट्टी की खुशबू ही काफी है।■

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक

किसानों को किसान–हित नीतियों से अवगत कराने का संकल्प

पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कि बैठक भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित कि गयी, जिसमें देश के सभी प्रान्तों के भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। इस बैठक में देश के किसानों की समस्या एवं केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों की किसान हित नीतियों के कार्यकर्मो को किसानों तक पहुचने का किसान मोर्चा ने कार्यक्रम लिया है। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के निर्देशानुसार किसान और खेतिहर मजदूर महिलाओं का प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना देश के हर विधान सभा क्षेत्र में 5000 की संख्या में किसान मोर्चा द्वारा पंजीकरण किया जायेगा।

इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किसानों के प्रति संवेदनशील बनकर सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करेगा और विपक्ष की किसान विरोधी नीतियों के सामने किसान मोर्चा आंदोलन व संघर्ष करे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल जैन ने प्रधानमंत्री की जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रत्येक क्षेत्र में अमल हो इस विषय में विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रभारी श्री सत्यपाल मालिक ने केन्द्र सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजयपाल सिंह तोमर ने किसान मोर्चा के सभी प्रदेश अध्यक्षों को अपने–अपने प्रदेशो में किसान मोर्चा के संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। ■
~~~~~~~~~~

बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज – 2015

प्रधानमंत्री की यह हमेशा से अवधारणा रही है कि बिहार में असीमित क्षमता है। यह पूरे देश को मजबूती प्रदान कर सकता है। भारत पूर्ण रूप से तभी विकसित होगा जब भारत के पूर्वी भाग का विकास होगा। प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि बिहार का विकास उनका महत्वपूर्ण एजेण्डा है।

विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक व्यापक पैकेज को स्वीकृति दी है। इस पैकेज में यह ध्यान रखा गया है कि सहायता के सारे स्रोत बिहार को आने वाले वर्षो में स्वावलंबी बनाने में मदद करें। समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए उसकी युवा पीढ़ी का स्वावलंब होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ समाज के वर्तमान के पालनकर्ता की आय को बढ़ाना भी आने वाली पीढ़ी को स्वावलंब बनाने में मदद करता है। इस पूरे पैकेज में युवा वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करना और किसान जोकि वर्तमान में बिहार के पालनकर्ता हैं, उनकी आय को बढ़ाने को मुख्य बिन्दु बनाया गया है।

किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि कृषि मंत्रालय को अब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

मनुष्य और उत्पाद का आवागमन जहाँ सरल तरीके से हो, विकास पहले उसी क्षेत्र का होता है। अत: इस पैकेज में बिहार के विकास के लिए रोड, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग तथा डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। कनेक्टिविटी स्थापित करने से बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा जोकि यहां के युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने में तथा किसानों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य दिलाने में काफी उपयोगी साबित होगा।

इस पैकेज में राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास, महत्वपूर्ण नदियों पर पुल का काम तथा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिये 54,713 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर एक नए पुल का निर्माण, कोसी ओर सोन नदी के ऊपर पुल का निर्माण, धार्मिक पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रेलवे ओवरब्रिजेज का निर्माण शामिल है।

भंडारण और यातायात सुविधा के अभाव में किसान अपने उत्पाद को कम दाम में बेचने पर मजबूर हो जाता है। इस पैकेज में अनाज भंडारण क्षमता में विकास के लिए 814 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण सड़क के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 22,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु 13,820 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

रेलवे के विकास के लिए बिहार में मुख्यतया चल रही ट्रेनों की गति को बढ़ाना एक चुनौती है। रेलवे सेवा को और तीव्र और बेहतर बनाने के लिए रेलवे दोहरीकरण/तीहरीकरण और विद्युतीकरण पर बल दिया गया है। 8109 करोड़ रु. की लागत पर 676 किलोमीटर का दोहरीकरण/तीहरीकरण की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है तथा 761 करोड़ रु. की लागत पर 574 किलोमीटर के विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया है। इस तरह रेलवे के क्षेत्र में कुल 8870 करोड़ रु. का प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। मोकामा में गंगा नदी के ऊपर रेल व रोड पुल के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य आरंभ कर दिया गया है।

बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को वायुमार्ग से देश और विदेश से जोड़ने हेतु पटना में नये एयरपोर्ट तथा गया, पूर्णिया और रक्सौल के एयरपोर्टों के विकास के लिए 2700 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाइल फोन की उत्तम सुविधा के लिए 1,000 नए बीटीएस टॉवर्स को स्थापित करने का प्रावधान है। इससे दूर के क्षेत्रों में जहाँ मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है, वहाँ इस सुविधा में मदद मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चर कलस्टर की स्थापना के लिए 150 करोड़ रु. की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

दरभंगा और भागलपुर में साफ्टवेयर

टेक्नोलॉजी पार्क के दो केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है। दो नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स ऐंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी केन्द्र मुजफ्फरपुर और बक्सर में स्थापित करने का भी प्रावधान है। इसके साथ-साथ पटना के वर्तमान केन्द्र के विकास का भी प्रावधान है। ग्रामीण बीपीओ को बढ़ावा देने का प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। कनेक्टिविटी के ये सारे कार्यक्रम बिहार राज्य को विकास की दौड़ में लाने के लिए एक ट्रैक-फील्ड का काम करेंगे।

इस पैकेज के द्वारा बिहार के किसानों की एक और व्यापक समस्या जोकि उत्पादकता का कम होना है, के समाधान हेतु भी ध्यान दिया गया है। नए अनुसंधान और विकास तथा लैब टू फार्म को बढ़ावा देने के लिए राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। मत्स्य पालन, पानी के सही प्रबंधन, खेती के यांत्रिकीकरण, और गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। एकीकृत कृषि पर शोध के लिए राष्ट्रीय संस्था का प्रावधान किया गया है।

युवा वर्ग को शिक्षा और कौशल

युवा वर्ग को उत्तम शिक्षा और स्किल डेवलेपमेंट प्रदान करना उनकी सफल भागीदारी के लिए आवश्यक तत्व हैं। युवा वर्ग की इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' के अंतर्गत एक लाख युवक-युवतियों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य में एक बड़े स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान है जिसकी कुल लागत 1,250 करोड़ रुपये होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भागलपुर के निकट ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जगह एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। साथ ही साथ बोध गया में एक नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम)की स्थापना का भी प्रावधान है। ट्रैक फील्ड के निर्माण के साथ-साथ सहभागियों को उत्तम दर्जे की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिये जाने के बाद प्रतिस्पर्धा को आरंभ कर लंबे समय तक कार्यान्वित करने के लिए राज्य को ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

इस पैकेज के द्वारा बिहार के किसानों की एक और व्यापक समस्या जोकि उत्पादकता का कम होना है, के समाधान हेतु भी ध्यान दिया गया है। नए अनुसंधान और विकास तथा लैब टू फार्म को बढ़ावा देने के लिए राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। मत्स्य पालन, पानी के सही प्रबंधन, खेती के यांत्रिकीकरण, और गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। एकीकृत कृषि पर शोध के लिए राष्ट्रीय संस्था का प्रावधान किया गया है।

बिहार के लोगों को बिजली की व्यवस्था

इस पैकेज में ऊर्जा का उत्पादन, ट्रांसमीशन और वितरण की व्यवस्था पर काफी बल दिया गया है। बक्सर में 1300 मेगावाट के नए बिजली उत्पादन केन्द्र का प्रस्ताव है।

गाँव में बिजली - बेहतर जीवन की सुविधा

इसके साथ-साथ गाँव-गाँव में बिजली की व्यवस्था पहुंचाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना में राज्य के लिए 5,880 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेतों में पर्याप्त और घरों में निरंतर बिजली देने का है। हर गांव में दो अलग-अलग लाइनों की व्यवस्था की जाएगी। इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत शहरों में निरंतर बिजली देने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य के लिए किया गया है।

महिलाओं को बेहतर ईंधन की सुविधा

हमारी माताओं और बहनों को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए घर-घर में रसोई गैस पहुंचाने पर इस पैकेज में बल दिया गया है। बिहार राज्य में गैस की आपूर्ति के लिए जगदीशपुर-हल्दिया लाइन के लिए 2,300 करोड़ रुपये की लागत से 617 कि.मी. की पाइप-लाइन बनाने का प्रावधान किया गया है। पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइप-लाइन का बिहार में विस्तार करने के लिए 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुजफ्फरपुर में 110 करोड़ रुपये की लागत से एक नए एलपीजी प्लांट की स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य में स्थित बरौनी रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता को 12,000 करोड़ रुपये की लागत से 6 मिलियन टन से 9 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रावधान इस पैकेज में है तथा बरौनी में ही एक पेट्रोकेमिकल प्लांट की स्थापना का प्रावधान है। रक्सौल से नेपाल में अमलेसगंज तक

पेट्रोल-डीजल पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा।

स्वास्थ्य की सुविधा

पटना, गया और भागलपुर के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन में रोजगार के अवसर

बिहार के युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने हेतु पर्यटन के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये की लागत से वैशाली, बोधगया, चम्पारण, विक्रमशिला, सुल्तानगंज, पटना इत्यादि जगहों पर हैरिटेज टूरिस्ट सर्किल के विकास का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक निवेश से रोजगार : युवा वर्ग को स्वावलम्ब बनाने की प्रक्रिया

राज्य के युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक यूनिट्स की स्थापना हो, यह सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए Income Tax Act में संशोधन कर बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट और मशीनरी की लागत में 15 प्रतिशत की राशि के बराबर टैक्स में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया गया है। यह कटौती 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बीच हुए निवेश पर लागू होगी।

इसके साथ ही साथ नए प्लांट और मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बीच पिछड़े क्षेत्रों में निवेश की 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि Depreciation Allowance के तौर पर पहले वर्ष में दी जाएगी।

प्रधान मंत्री के इस विशेष पैकेज के अंतर्गत आने वाले वर्षों में बिहार में 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं लागू करने का प्रावधान है।

बिहार राज्य की ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए निजी क्षेत्र को भी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भागीदार बनाया जा रहा है। बांका में 4,000 मेगावाट का एक अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लांट निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ 20,000 करोड़ रु. की लागत पर प्रस्तावित है।

वर्ष 2013 में 12,000 करोड़ रु. की लागत से बिहार के लिए एक स्पेशल प्लान की घोषणा की गई थी। सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अब तीव्रता लाई गई है। बचे हुए कार्यक्रमों को 8,282 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराकर पूरा किया जाएगा।

वर्तमान में चल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बिहार में 1 करोड़ 34 लाख नये अकाउंट खोले गए और 1 करोड़ 23 लाख खाताधारकों को रु-पे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में 1680 करोड़ रुपये की राशि लोगों ने अब तक जमा की है।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बिहार में 21,00,099 लोगों का एनरोलमेंट किया गया है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 11,25,073 लोगों को बिहार राज्य में इनरोल किया गया है। अटल पेंशन योजना का लाभ 33,760 लोग उठा रहे हैं।

नए और छोटे उद्यमियों को बैंक लोन

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिहार में 1 लाख से ज्यादा मुद्रा उद्यमियों को 868 करोड़ रुपये की राशि मुद्रा लोन के रूप में उपलब्ध कराई गई है। यह राशि 4 महीनों के दौरान उपलब्ध कराई गई है। बिहार राज्य में 6 हजार 292 बैंक शाखाएं हैं। प्रधान मंत्री की 15 अगस्त की उद्घोषणा के अनुसार 6292 महिला उद्यमियों और 6292 दलित उद्यमियों को स्टार्टआ व स्टैंडअप योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

स्वच्छ विद्यालय

स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत जहां पूरे देश में 4 लाख 17 हजार 756 शौचालयों का निर्माण विद्यालयों में हुआ है उनमें से 56 हजार 912 शौचालय बिहार में बने हैं।

सवा लाख करोड़ के नए पैकेज, चालीस हजार करोड़ के अतिरिक्त निवेश, सामाजिक सुरक्षा के व्यापक कार्यक्रमों और टैक्स में छूट के द्वारा औद्योगीकरण को बढ़ावा देने से बिहार में विकास के नए युग का आरंभ होगा। ■

प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बिहार में 1 करोड़ 34 लाख नये अकाउंट खोले गए और 1 करोड़ 23 लाख खाताधारकों को रु-पे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में 1680 करोड़ रुपये की राशि लोगों ने अब तक जमा की है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बिहार में 21,00,099 लोगों का एनरोलमेंट किया गया है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 11,25,073 लोगों को बिहार राज्य में इनरोल किया गया है। अटल पेंशन योजना का लाभ 33,760 लोग उठा रहे हैं।

बिहार एक स्वावलंबी राज्य बने : अमित शाह

1.25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के साथ पूर्व में चलनेवाली योजनाओं के लिए आवंटित 40 हजार करोड़ रुपये सहित 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा का किया स्वागत

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के साथ पूर्व में चलनेवाली योजनाओं के लिए आवंटित 40 हजार करोड़ रुपये सहित 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा का स्वागत किया।

भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि बिहार में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यही नहीं, वहां की जनता में असीमित क्षमता भी है। यदि इन संभावनाओं और क्षमता को सही दिशा मिले तो इससे न केवल बिहार की जनता का विकास होगा बल्कि पूरे देश को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि बिहार सहित पूर्वी भारत के सभी राज्यों को वे सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके और देश आगे बढ़ सके।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की स्वीकृति दी है जिससे बिहार स्वावलंबी राज्य बन सके, युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके फिर चाहे किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, दलित-शोषित और पिछड़ा वर्ग हो, सभी को चहुंमुखी विकास के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत इस पैकेज में बिहार की आम जनता की बुनियादी सुविधाएं- बिजली, सड़क और पानी के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इस पैकेज में बिहार के विकास के लिए सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग तथा डिजिटल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई है ताकि कनेक्टिविटी बढ़ने से बिहार में जहां उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा वहीं युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध होंगे तथा किसानों को उनके उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए जो कदम उठाए गए हैं यदि राज्य सरकार उसे सही रूप से अमली जामा पहनाती है तो बिहार शीघ्र ही विकास के पथ पर बढ़ चलेगा और देश के विकास में विशेष भागीदारी सुनिश्चित करेगा तथा बिहार से युवा एवं श्रम शक्ति के पलायन में रोक लगेगी।

किंतु आज जो बिहार के राजनीतिक दल मुख्यत: जदयू और आरजेडी के लोग दलगत राजनीति की मानसिकता से ग्रसित होकर चुनावी लाभ के लिए इस पैकेज का बेवजह विरोध कर रहे हैं वे बिहार के पैकेज का नहीं, बल्कि बिहार के विकास का विरोध कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री शाह ने कहा कि बिहार की जनता को विचार करना चाहिए कि यह राजनीतिक दल इस तरह से केंद्र द्वारा बिहार के विकास के लिए उठाए गये कदमों का विरोध करते हैं तो बिहार का विकास कैसे संभव होगा? आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन दलों को करारा जवाब देगी। ■

केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए जो कदम उठाए गए हैं यदि राज्य सरकार उसे सही रूप से अमली जामा पहनाती है तो बिहार शीघ्र ही विकास के पथ पर बढ़ चलेगा और देश के विकास में विशेष भागीदारी सुनिश्चित करेगा तथा बिहार से युवा एवं श्रम शक्ति के पलायन में रोक लगेगी। किंतु आज जो बिहार के राजनीतिक दल मुख्यत: जदयू और आरजेडी के लोग दलगत राजनीति की मानसिकता से ग्रसित होकर चुनावी लाभ के लिए इस पैकेज का बेवजह विरोध कर रहे हैं वे बिहार के पैकेज का नहीं, बल्कि बिहार के विकास का विरोध कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

क्या यह भारत का नुकसान है?

– अरूण जेटली

संसद का तयशुदा मानसून सत्र संपन्न हो गया। राजनीतिक रूप से यह सत्र काफी शिक्षा प्रदान करने वाला लेकिन निराशा भरा था। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्वकर्ता है पर बिना किसी एक मुद्दे के 'संसदीय कार्रवाही का बाधित होना' संसदीय व्यवस्था में भेद्यता को रेखांकित करता है।

जीएसटी के महत्व को अतिरंजित नहीं होना चाहिए। यह पूरे देश को एक आर्थिक बाजार में बदलता है। यह माल और सेवाओं की सहज और निर्बाध रूप से आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। यह परेशानी और भ्रष्टाचार को कम करता है। यह एक समान कर व्यवस्था को प्रतिपादित करता है तथा 'कर के ऊपर कर' की अवधारणा को समाप्त करता है। इससे कर राजस्व में उछाल आता है और सकल घरेलू उत्पाद पर एक अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जीएसटी को देश की मुख्यधारा की अधिकतम राजनीतिक पार्टियों का लगातार समर्थन प्राप्त हुआ है। कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार ने 2006 में जीएसटी की अवधारणा की घोषणा की थी और इस विधेयक को 2011 में पेश किया गया था। आज जीएसटी पर कांग्रेस अपने कदम वापस खींच कर रही है। कांग्रेस पार्टी की असहमति – टिप्पणी की आपत्तियां विरोधाभासी और तुच्छ हैं। इस मुद्दे पर संसद का बहुमत कांग्रेस के खिलाफ है। इसलिए इसका पारित होना राज्य सभा द्वारा इस पर मीमांसा को केवल रोकने के उद्देश्य से बिना किसी कारण इख्तियार किये गए अशांति और वाकयुद्ध पर निर्भर करता है। कांग्रेस इस बात से स्पष्ट रूप से अवगत है कि संविधान संशोधन के पारित होने में किसी भी तरह की देरी इस विधेयक को कम-से-कम एक वर्ष के लिए विलम्बित कर देगी जिसको कि अधिकतम राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इससे कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट हो जाती है। उनकी प्राथमिकता सूची में राष्ट्रीय हित सबसे नीचे है।

यह सत्र आम लोगों की इस राय पर प्रकाश डालता है और बतलाता है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा द्वारा भारत के आर्थिक हितों का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया है।

कांग्रेस पार्टी ने यह प्रदर्शित किया है कि लगातार ये सारी चीजें एक परिवार का गुलाम बनकर रह गई हैं। यह राष्ट्रीय हित और नीतिगत मुद्दों पर भी समझौता के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कांग्रेस अब तक 2014 में मिली अपनी अप्रत्याशित चुनावी हार को पचा नहीं पाई है। इस सत्र में भारत का नुकसान कांग्रेस पार्टी का लाभ कतई नहीं हो सकता। इनके 'बिना किसी एक कारण के बिना संसद में व्यवधान' की नीति के खिलाफ जनमत में लोकप्रिय अस्वीकृति है। लोक सभा में पिछले दिनों की बहस कांग्रेस पार्टी के तर्क के खोखलेपन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर देता है।

कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इस सत्र में सदन में निम्नतम मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब मुख्यधारा की एक पार्टी के सर्वोच्च नेता ने सदन के वेल में आकर हंगामे का नेतृत्व किया हो। उन्होंने तो अपने कद और गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो इस बात की कोई गंभीर उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह बहस के स्तर को उठा पाएंगें। वह नारेबाजी और एक संसदीय भाषण के बीच के अंतर को पहचान पाने में नाकाम रहे हैं। जिस तेजी से वह आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से वह और अधिक अपरिपक्व होते जा रहे हैं। आक्रामक शारीरिक भाषा तर्कसंगत निष्कर्ष का विकल्प कदापि नहीं हो सकती। यह राजग सरकार है जिसने अवैध विदेशी सम्पत्तियों के खिलाफ कड़े कानून बनाये। यह राजग सरकार है जो वर्तमान विवाद के केंद्र में रहे आरोपी अपराधी को सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

यह सत्र आम लोगों की इस राय पर प्रकाश डालता है और बतलाता है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा द्वारा भारत के आर्थिक हितों का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया है। भारतवर्ष इस पर एक साथ खड़ा है हालांकि थोड़ा निराश है। इस हताशा से उभरता विरोध देश को इस चुनौती का सामना करने के लिए सम्बल प्रदान करेगा। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं।)

लेख

व्यष्टि व समष्टि और एकात्म मानववाद

– डॉ. विजेन्द्र सिंह गुप्त

इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न विचारक प्रारम्भ से ही करते आये हैं कि व्यक्ति व समाज के आदर्श संबंध क्या हों। आदर्श संबंधों की खोज में कभी विचारकों ने व्यष्टि को और कभी समष्टि को महत्व दिया है। व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति को साध्य माना है और समाज को साधन। समाजवादियों ने समाज को साध्य मानकर व्यक्ति को उसका साधन माना है। मतभेद इसी बात पर रहा है कि व्यक्ति और समाज में से कौन साध्य हो और कौन साधन हो। साध्य और साधन की स्थिति एक को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न बना देती है। जो साध्य होगा, वह अधिक महत्वपूर्ण होने का दावा करेगा और जो साधन होगा, वह हीनता के भाव से समाविष्ट हो जायेगा। यह स्थिति संघर्ष की स्थिति है। संघर्ष की स्थिति को यदि समाप्त करना है या उस स्थिति का निर्माण ही नहीं होने देना है तो साध्य व साधन, महत्वपूर्ण व महत्वहीन या श्रेष्ठ व निम्न के संबंधों को ही भुलाना होगा। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने उचित ही कहा है कि ''व्यक्ति और समाज में विरोध मानना ही भूल है। विकृतियों की, अव्यवस्था की बात छोड़ दें। उसे दूर करने के उपाय करने भी आवश्यक होते हैं, किन्तु मूल सत्य यही है कि व्यक्ति और समाज अभिन्न और अविभाज्य हैं। सुसंस्कृत अवस्था वही है जहां व्यक्ति अपनी चिंता करते हुए भी समाज की चिंता करेगा। दोनों में समन्वय की स्थिति है। समाज का बिगाड़ करके अपनी भलाई करने का विचार जो करेगा, वह गलत सोचेगा। यह विकृत अवस्था है। इसमें उसका भी भला नहीं होने वाला, क्योंकि समाज जिस स्थिति में पहुंचेगा, उसे व्यक्ति को ही भोगना पड़ेगा।''

व्यष्टि व समष्टि को पृथक-पृथक करके नहीं देखा जा सकता। भारतीय विचारकों ने इन दोनों को समग्र रूप में देखा व जाना।

''हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो व्यष्टि की उपासना करता है, वह अंधकार को प्राप्त होता है और जो केवल समष्टि की उपासना करता है, वह भी अंधकार में पड़ता है। भारतीय पद्धति के अनुसार दोनों का समन्वय चाहिए। व्यष्टि की उपासना कर मृत्यु को जीतना चाहिए और समष्टि की उपासना कर अमरता प्राप्त करनी चाहिए। व्यष्टि को समष्टि में विलीन करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। व्यक्ति (व्यष्टि) मरणशील है, जबकि समष्टि अमर है।''

समाज की समस्याओं को समग्र रूप में देखना होगा

व्यक्तिवाद यदि व्यक्ति को महत्व देकर आदर्श स्थिति की कल्पना करता है तो समाजवाद समाज व समष्टि को महत्व देकर आदर्श स्थिति की कल्पना करता है। पाश्चात्य विचारकों ने आदर्श स्थिति की खोज में एक समग्र समस्या को अनेक टुकड़ों में बांटकर भिन्न-भिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु अपने सुझाव दिये। इस विभाजन ने समस्या को सुलझाने के स्थान पर और जटिल बना दिया। समाज की समस्याओं को वर्गीकृत करके या विभाजित करके देखना ऐसा ही है जैसे किसी सावयव के रोग को समग्र रूप में न देखकर अलग-अलग अंगों की व्याधि के रूप में देखा जाय। सिर में पीड़ा हुई और उसके उपचार हेतु एक औषधि का सेवन किया गया। पेट में पीड़ा हुई और उसके उपचार हेतु एक अन्य औषधि का सेवन किया गया। सिर की पीड़ा की औषधि पेट के लिये हानिकर सिद्ध हुई और पेट की पीड़ा की औषधि सिर के स्वास्थ्य के लिये घातक सिद्ध हुई। यह इसीलिये हुआ कि उपर्युक्त दोनों रोगों को पृथक-पृथक करके देखा गया, जबकि वास्तव में ये दोनों रोग एक ही रोग के दो अलग-अलग परिणाम हैं।

चिकित्सा का अभीष्ट किसी एक अंग के रोग को समाप्त करना नहीं, बल्कि समग्र सावयव को नीरोग व स्वस्थ करना है। समाज की एक समस्या का निराकरण यदि खोज भी लिया जाये तो कोई आवश्यक नहीं कि समाज पूरी तौर से स्वस्थ हो ही जायेगा। एक समस्या का निराकरण अन्य नयी समस्या को जन्म दे सकता है। निरक्षरता को समाप्त करने के लिये असंख्य विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय खोल दिये गये। क्या उनकी स्थापना से समाज की समस्याएं सुलझ गयीं? समस्याएं सुलझने के स्थान पर और जटिल हो गयीं और शिक्षित लोगों की भीड़ ने अन्य अनेक समस्याओं को जन्म दे दिया। किसी एक राज्य में सर्पों की संख्या बहुत बढ़ गयी। इससे जनता को कष्ट होना प्रारंभ हुआ। राजा ने सूचना प्रसारित करा दी कि जो सर्प मारकर लायेगा उसको पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार प्राप्त करने की होड़ लग गयी, जिसने कुछ सामाजिक दोष उत्पन्न कर

दिये। अन्य दोष सर्पो के अभाव से यह उत्पन्न हो गया कि चूहों की संख्या में भयानक वृद्धि होने लगी।

इसी प्रकार व्यक्ति ने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक उन्नति की दिशा मैं दौड़ लगानी प्रारंभ की और आर्थिक सम्पन्नता ने कितनी ही सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म दे डाला। हमारा अभीष्ट जब व्यक्ति व समाज को अधिकतम संतोष पहुँचाना व उनका अधिकतम कल्याण करना है तो उनकी समस्याओं को टुकड़ों-टुकड़ों में विभाजित करके देखने व उनका पृथक-पृथक निराकरण करने से कोई लाभ नहीं होगा।

यद्यपि पाश्चात्य विचारकों को यह श्रेय अवश्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र अध्ययन-विषय के रूप में प्रस्तुत किया, परन्तु इस बात पर विचार करना भी अपेक्षित है कि इससे मानव-कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ा? यदि राजनीतिक विषयों पर विचार करना ही अभीष्ट होता तो यह स्वीकार किया जा सकता था कि पाश्चात्य विद्वानों ने पृथक विषय की स्थापना द्वारा बहुत प्रशंसनीय कार्य किया। परन्तु वास्तविकता यह है कि मात्र विचार करना ही अभीष्ट न उस समय था और न इस समय है। अभीष्ट तो यह है कि एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की खोज की जाये जो मानव का अधिकतम कल्याण कर सके। समाज की समस्त समस्याएं एकीकृत हैं। बातों को अलग-अलग देखने की प्रवृत्ति ने विशिष्टीकरण को जन्म दिया है जो बड़े अंशों में समाज के विघटन का कारण बना है। इस कारण पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के अपने सिद्धान्त के अन्तर्गत राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याओं को अलग-अलग देखने और उनका अलग-अलग हल खोजने का विरोध किया है।

राष्ट्र एक सावयव है

राष्ट्र व समाज के किसी एक अंग पर स्वतंत्र रूप से पूर्ण विचार नहीं किया जा सकता। ये समस्त अंग एक दूसरे पर आश्रित हैं। सब व्यक्ति एक दूसरे पर उसी प्रकार आश्रित हैं, जिस प्रकार शरीर के अंग एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और सब व्यक्ति समाज से इसी प्रकार जुड़े हुए भी हैं, जैसे विभिन्न अंग शरीर से जुड़े हुए हैं। सब अंगों का व शरीर का एक सा ही महत्व है। यदि कोई अंग स्वयं की ही परवाह करता हो और अन्यों की परवाह न करता हो तो इससे उत्पन्न हानि से वह स्वयं भी नहीं बच पाता। जब व्यक्ति समाज के प्रति कर्तव्य का पालन न करते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिये कार्य करता है तो वह भूल जाता है कि प्रकारान्तर से वह स्वयं को ही हानि पहुंचा रहा है। किन्तु जब तक स्पष्ट हानि उसको नहीं होती, वह लाभ के भ्रम में रहता है। औषधियो में मिलावट करने वाला अन्यों को कष्ट पाते देखकर मिलावट करना नहीं छोड़ता। उसकी आखें तब खुलती हैं जब मिलावटी औषधि के उपयोग से उसका अपना स्वजन ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। प्रत्यक्ष में हानि होने तक व्यक्ति का यह भ्रम बना रहता है कि अन्यों को भले ही हानि हो, उसको तो लाभ ही है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। शरीर के एक अंग की अस्वस्थता का प्रभाव उसी अंग तक सीमित नहीं रहता। वह दूसरे अंगों की अस्वस्थता का भी कारण बन जाता है। इसी प्रकार समाज के एक व्यक्ति का पिछड़ापन समाज के अन्य लोगों के पिछड़ेपन का कारण बनता है।

व्यक्ति की प्रकृति के समान राष्ट्र की भी एक विशिष्ट प्रकृति है

प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित प्रकार का स्वभाव होता है। कोई क्रोधी स्वभाव का होता है तो कोई शान्त स्वभाव का। कोई नम्र होता है तो कोई अंहकारी। कोई अन्तर्मुखी होता है तो कोई बहिर्मुखी। ''..... किसी राष्ट्र के सभी नागरिकों की इच्छाओं का योग राष्ट्र की इच्छा नहीं कही जा सकती। यद्यपि अधिकांश मामलों में दोनों एक जैसी हो सकती हैं, राष्ट्र की इच्छा उसके नागरिकों की इच्छा से बिल्कुल अलग राष्ट्र की अपनी 'इच्छा' होती है, क्योंकि राष्ट्र की उसके नागरिकों के समूह से अलग अपनी एक सत्ता होती है? और प्रत्येक सत्तावान वस्तु की अपनी इच्छा होती है।'' राज्य या राष्ट्र का भी इसी प्रकार एक स्वभाव या प्रकृति होती है। यदि व्यक्ति प्रगति करता है तो स्वभाव के अनुकूल ही प्रगति करता है। इसी प्रकार राष्ट्र आगे बढ़ता है तो एक निश्चित मार्ग पर ही आगे बढ़ता है। यदि व्यक्ति को कोई व्याधि लगती है तो उसका उपचार उसकी प्रकृति को ध्यान में रखकर करने से ही लाभ होता है। आयुर्वेदिक उपचार-पद्धति में वात, पित्त व कफ की प्रकृति के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। उपचार हेतु व्यक्ति की प्रकृति पर अवश्य ध्यान देना होता है। एक रोग की एक निश्चित व निर्दिष्ट औषधि है। वह रोग उस औषधि से ठीक हो सकता है, किन्तु यदि व्यक्ति की प्रकृति के प्रतिकूल है तो औषधि प्रभावकारी नहीं होती।

भारत पर एक लम्बे समय तक विदेशियों का आधिपत्य रहा। भारत की समस्याओं का निदान वैदेशिक अनुभवों के आधार पर किया गया। विदेशियों द्वारा भारत छोड़कर जाने के उपरान्त भी वैदेशिक सूत्रों के माध्यम से समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई।

कुछ मामलों में तो वैदेशिक हल भारत की 'चिति' के अनुकूल सिद्ध

हुए, परन्तु अनेक ऐसे मामले भी रहे जहाँ वैदेशिक सूत्र भारत के लिये पूरी तरह प्रतिकूल सिद्ध हुए। आज के भारत की समस्याओं का एक बड़ा कारण यही तथ्य है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने उचित ही कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात् भी भारतीय नेतृत्व ने व्यक्ति की सामाजिक भूमिका का उचित व सही ज्ञान नहीं कराया, उन्होंने पाश्चात्य विचारों को भारतीय संदर्भ में उतारने का प्रयास किया। देश की समस्याओं को सुलझाया न जा सका, बल्कि समस्याएं बढ़ती ही चली गयीं।

भारत के स्वातन्त्र्योत्तर विचारकों की भी यह दुर्बलता रही कि वे भारत की प्रकृति के अनुकूल भारत की समस्याओं का हल नहीं निकाल पाये। इस दुर्बलता का भी एक बड़ा कारण भारतीय विचारकों पर पाश्चात्य प्रभाव का अतिरेक था, जबकि भारत की समस्याओं का निदान भारत की मिट्टी में से ही खोजा जाना अपेक्षित था।

क्रमशः...

(दीनदयाल शोध संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका 'मंथन-जुलाई 1979' से साभार)

कांग्रेस का असंसदीय रवैय्या दुर्भायिपूर्ण : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी की संसद के पिछले मानसून सत्र में कांग्रेस के विकास विरोधी, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तथा असंसदीय रवैय्ये के खिलाफ सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रेस वार्ता

भारतीय जनता पार्टी ने संसद के पिछले मानसून सत्र में कांग्रेस के विकास विरोधी, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तथा असंसदीय रवैय्ये के खिलाफ भारत-वर्ष के हरेक राज्यों में प्रेस वार्ता की तथा देश की जनता को कांग्रेस के नकारात्मक और जन-विरोधी राजनीति से अवगत कराया। भाजपा ने देश भर के लगभग 28 राज्यों में प्रेस कांफ्रेंस के जरिये न केवल कांग्रेस की तुच्छ राजनीति पर हमला बोला वरन कांग्रेस के जन - विरोधी तथा असंसदीय व्यवहार के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए जमकर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य संसद की कार्यवाही को रोकना है।

भाजपा ने कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछले लोक सभा चुनावों से भी बड़ी राजनीतिक अधोगति होने वाली है। भाजपा ने कांग्रेस के असंसदीय व्यवहार पर निशाना साधते हुए कहा कि असंसदीय और अलोकतांत्रिक रवैय्ये को इस मानसून सत्र में सम्पूर्ण भारतवर्ष की जनता ने देखा है और वह कांग्रेस को तगड़ा सबक सिखाएगी।

ज्ञात हो कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इससे पहले के तीन संसदीय सत्र में लोक सभा में औसतन 108 प्रतिशत कार्य हुए थे जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लेकिन कांग्रेस राजग सरकार की जबरदस्त उपलब्धियों को पचा नहीं पा रही है और उसे इस बात का डर लगातार सता रहा है कि अपने प्रदर्शन के बल पर भाजपा कहीं सारी वाहवाही न ले जाए और वह पूरी तरह से राजनीतिक हाशिये पर न पहुँच जाए।

भाजपा की ओर से लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने देहरादून में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा ने चंडीगढ़ में, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने बेंगलुरू में, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यीमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने हैदराबाद में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने लखनऊ में, केंद्रीय कोयला व ऊर्जा मंत्री श्री पियूष गोयल ने अहमदाबाद में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री श्री सर्बानंद सोनवाल ने डिब्रूगढ़ में तथा पार्टी के प्रवक्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों ने भी विभिन्न राज्यों में प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया।

इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने रायपुर में, गोवा के मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पंजिम में, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में, झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने रांची में तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने मुंबई में प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया।

वहीं दिल्ली के भाजपा केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया। ■

नगरीय निकाय चुनावों में खिला कमल

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की सोलहों नगरनिगमों पर और 42 नगर पालिकाओं तथा 123 नगर पंचायत परिषदों पर भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है।

चुनावों में पार्टी ने कांग्रेस से मुरैना, हरदा, भैंसदेही, सुवासरा, कोटर,चाकघाट, छीनकर कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर सिमटाकर रख दिया है। पूर्व में नगर पालिका मुरैना पर कांग्रेस काबिज थी, नगरनिगम गठित होने के बाद यह पहला चुनाव था। इस चुनाव में मुरैना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। प्रदेश में पहली बार गठित मुरैना नगर निगम परिषद और उज्जैन नगर निगम परिषद में भी पार्टी को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है।

देश की जनता ने कांग्रेस को उसकी चरित्र हनन की राजनीति के लिए दंडित किया है और कांग्रेस सिर्फ सारंगपुर में अपनी इज्जत बचा पाई है और बाकी जगह कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया हैं।

यह मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विकासोन्मुखी कार्यक्रमों, सुशासन और विकास की विजय है।

नगरीय निकायों में भाजपा की विजय पार्टी की विचारधारा, प्रधानमंत्री के क्रांतिकारी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मध्य प्रदेश के प्रभारी, श्री विनय सहस्रबुद्धे और मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव में मिली यह जीत दर्शाती है कि जनता ने श्री शिवराज के प्रति विश्वास और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।

मध्यप्रदेश में लगातार एक के बाद एक चुनाव में जनता ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की नीति, नियत पर विश्वास व्यक्त किया है और जनता का यह अथाह विश्वास आज भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति कायम है। ■

निकाय चुनाव में जीत पर बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा जताने के लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा को मिली जीत से वे बेहद खुश हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी इस जीत के लिए बधाई दी।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राज्य की जनता, संगठन पदाधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत वास्तव में विकास और सुशासन की जीत है। ■

राजस्थान

हाल ही में हुए राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा ने 129 में से 87 निकायों पर भारी जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस महज 38 निकायों में ही जीत हासिल कर सकी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने बीकानेर की नोखा नगर पालिका पर जीत हासिल की। चुनाव नतीजे पर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि निकाय चुनाव में वोटरों ने हमारे अच्छे शासन पर मुहर लगाई है। डेढ़ साल के शासनकाल में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। गौरतलब है कि इस जीत पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बधाई दी। ये चुनाव 17 अगस्त को हुए थे और चुनाव परिणाम 20 अगस्त को घोषित किए गए।

बॉक्स

परिणाम एक नजर में
कुल वार्ड- 3351
भाजपा- 1437
कांग्रेस-1162
निर्दलीय व अन्य-703

कुल स्थानीय निकाय-129
भाजपा-87
कांग्रेस-38
निर्दलीय-4
राकांपा-1

नगर निगम
अजेमर-भाजपा जीती